बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 96 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 23 जनवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

अगले 2 दिनों तक गरज-चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी, पड़ेगी कड़ाके की ठंड

नई दिल्ली। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच अब मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 23 और 24 जनवरी के आसपास पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश, तेज हवाएं और कोहरे का असर देखने को मिलेगा, जिससे तापमान में फिर गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 23 जनवरी को दिल्ली-एनसीआर में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं 24 जनवरी को अधिकतम तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है।

अरुण शर्मा लक्की हिन्दुस्तानी अमॅच्योर जीत कुनो डो एसोसिएशन ऑफ दिल्ली के सर्वसम्मति से दिल्ली राज्य अध्यक्ष चुने गए

नई दिल्ली।

नई दिल्ली में जीत कुनो डो मार्शल आर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं अमॅच्योर जीत कुनो डो एसोसिएशन ऑफ दिल्ली (रजि.) के तत्वावधान में एक भव्य एवं अत्यंत गरिमामय नियुक्ति समारोह एवं वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम खेल, समाज और राष्ट्र निर्माण की भावना से ओतप्रोत रहा। आयोजित वार्षिक आम सभा में फेडरेशन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने राष्ट्रीय महासचिव श्री विकास गिहरा के नेतृत्व तथा चुनाव अधिकारी की उपस्थिति में श्री अरुण शर्मा, जिन्हें लोकप्रिय रूप से लक्की हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता है, को सर्वसम्मति से दिल्ली राज्य अध्यक्ष चुना। इस अवसर पर फेडरेशन के पदाधिकारियों ने अपने संबोधन में खेलों के विकास की विस्तृत एवं दूरदर्शी रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि नवनियुक्त माननीय दिल्ली राज्य अध्यक्ष श्री अरुण शर्मा ÷लक्की हिंदुस्तानी÷ के नेतृत्व में आने वाले समय में युवाओं को खेलों से जोड़ने, मार्शल आर्ट्स एवं भारतीय पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने, तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए ठोस, योजनाबद्ध एवं प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली राज्य अध्यक्ष चुने जाने के बाद अपने संबोधन में श्री अरुण शर्मा लक्की हिंदुस्तानी ने समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, फेडरेशन के पदाधिकारियों, सदस्यों एवं जनसमूह का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार एवं दिल्ली सरकार द्वारा खेलों के विकास हेतु संचालित खेलो इंडिया, फिट इंडिया सहित अन्य विभिन्न सरकारी योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि फेडरेशन आगामी दिनों में इन योजनाओं की जानकारी प्रत्येक खिलाड़ी तक पहुँचाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध

है। साथ ही उन्होंने भारतीय पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने एवं उन्हें सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त खेलों की श्रेणी में शामिल करवाने के लिए निरंतर प्रयास करने का संकल्प भी दोहराया। उल्लेखनीय है कि श्री अरुण शर्मा ÷लक्की हिंदुस्तानी÷ विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों में अग्रणी भूमिका निभाते हुए लंबे समय से राष्ट्र एवं समाजहित में निरंतर सक्रिय रूप से कार्यरत रहे हैं। उनकी नियुक्ति को खेल जगत में एक सकारात्मक, प्रेरणादायी एवं दूरगामी कदम के रूप में देखा जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान पंजाबी सभा के चेयरमैन श्री नरेन्द्र मेहता (पप्पी) एवं प्रधान श्री प्रवीण मदान के नेतृत्व में सभा के सदस्यों अनिल खुराना, अजय सचदेवा, कमल बाली, पवन शर्मा, मनीष ग्रोवर, नितिन लखनपाल, बी. एस. मक्कड़, अजीत मक्कड़, सुशील खन्ना, तरुण अरोड़ा द्वारा श्री अरुण शर्मा का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न खेल संगठनों एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया। समारोह में देश के अनेक प्रतिष्ठित अतिथियों एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य महानुभावों की उपस्थिति रही। प्रमुख रूप से पंडित भोलानाथ शुक्ला, पवन सचदेवा, अश्वनी मल्होत्रा, विवेक गौर, दीपक भारद्वाज, सागर माथुर, चिरायु सिंह त्रेहन, मधु दास, अंजू तोमर, सतीश शर्मा, जगदीश ठेकेदार, विपुल खण्डेलवाल, विक्रम कपूर, दीपक झा, मीनू सागर, राम कुमार गुप्ता अजय मेहरा, वी. के. शर्मा, सुभाष व्यास, सुषमा शर्मा, धीरज पांडेय, सपना, पुनीत गांधी, राज कुमार दुबे, महावीर, अरुण मल्होत्रा, गौरव गोयल, जिनेश जैन, रामचंद्र ठाकुर, कनिका टंडन, विवेक टंडन, आशु गुप्ता सहित अनेक विशिष्ट व्यक्तित्व उपस्थित रहे। इसके साथ ही अमॅच्योर जीत कुनो डो एसोसिएशन ऑफ दिल्ली (रजि.) एवं जीत कुनो डो मार्शल आर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों एवं सदस्यों में नीरज सूद, सुमन चौधरी, ज्वलंत कुमार , जगदीश प्रसाद, परी शर्मा, खुशी, वाणी शर्मा, वैभव अरोड़ा, इब्राहिम खान, सविता, पर्व, मुन्नवर, अखिल खान, योगेश, मृदुल चौहान एवं पीयूष पाल की सक्रिय एवं सराहनीय सहभागिता रही। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य महानुभावों एवं फेडरेशन के सदस्यों ने श्री अरुण शर्मा को दिल्ली राज्य अध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक बधाई दी तथा उनके नेतृत्व में देश एवं दिल्ली राज्य में खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास और प्रोत्साहन की शुभकामनाएँ व्यक्त कीं कार्यक्रम का समापन शुभकामनाओं एवं राष्ट्र, खेल एवं समाज के समग्र विकास के संकल्प के साथ किया गया।

शराब घोटाले से जुड़े 2 केस में केजरीवाल को बड़ी राहत, अदालत ने बरी किया

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आज पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन का पालन न करने के मामलों में बरी कर दिया। राउज़ एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने फैसला सुनाया। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जारी समन का पालन न करने के लिए उनके खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। ईडी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने जांच में शामिल होने के लिए जारी किए गए समन का जानबूझकर पालन नहीं किया। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ समन का पालन न करने के आरोप में दो आपराधिक शिकायतें दर्ज की थीं।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 2 नवंबर और 21 दिसंबर 2023 तथा 3 जनवरी और 18 जनवरी 2024 को जारी किए गए ईडी के समन में उपस्थित नहीं हुए थे। उन्होंने इन समन नोटिसों को अवैध बताया था। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार किया था। उन्हें 20 जून, 2024 को राउज़ एवेन्यू कोर्ट की अवकाशकालीन न्यायाधीश नियाय बिंदु ने जमानत दे दी थी। ईडी की चुनौती पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी। जुलाई 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को उच्च पीठ के पास भेज दिया। ईडी ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को कुछ निजी कंपनियों को थोक व्यापार में 12 प्रतिशत का लाभ देने की साजिश के तहत लागू किया गया था, हालांकि मंत्रिपरिषद (जीओएम) की बैठकों के कार्यवृत्त में ऐसी कोई शर्त दर्ज नहीं थी। एजेंसी ने यह भी दावा किया था कि विजय नायर और अन्य व्यक्तियों ने साउथ ग्रुप के साथ मिलकर थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन देने की साजिश रची थी।

आप कभी चायवाला थे क्या? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी को लेकर दिया बड़ा बयान

नई दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने गुरुवार को कहा कि पीएम मोदी खुदको हमेशा से ही चायवाला बताते रहे हैं. लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या सही में वो कभी चायवाला रहे थे. क्या कभी उन्होंने चाय बनाई है? खरगे ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने हमेशा खुदको चायवाला इसलिए बताया ताकि वो इसका फायदा चुनाव में ले सकें. मैं तो उसने पूछना चाहता हूं कि क्या कभी उन्होंने ट्रेन में चाय बेची थी? उन्होंने आगे कहा कि ये दो लोगों की सरकार है. इनको कुछ नहीं पता है. ये सिर्फ चुनाव प्रचार में घूमते रहते हैं. इन्हें देश के लिए काम करना चाहिए. आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी को लेकर कोई बयान दिया हो. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था. उस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी के देशद्रोहीवाली टिप्पणी पर पलटवार किया था. उन्होंने कहा था कि गद्दार वे हैं हम नहीं है. हम देश के हित में जो भी उचित होगा,वह करेंगे, लेकिन हम आतंकवादियों, घुसपैठियों या किसी और का समर्थन नहीं करेंगे. खरगे ने कहा था कि जी राम जी बिल के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं. हमने प्रत्येक राय और जिले में

अपने लोगों को पहले ही बता दिया है कि आंदोलन जारी रहना चाहिए. इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए. कई और विपक्षी दल भी हमारा समर्थन कर रहे हैं. कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा था कि मनरेगा गरीबों के लिए जीवन रेखा है. वे जानबूझकर इसे खत्म कर रहे हैं और गरीब ग्रामीणों और खेतिहर मजदूरों को अमीरों का गुलाम बनाना चाहते हैं. इसीलिए हमने एमएनआईजीए कानून को बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ी, और इसके सभी प्रावधान यथावत रहने चाहिए. मैं नए कानून की निंदा करता हूं, जो केवल सरकार की मदद कर रहा है।

दिल्ली को मिलेगी नई थोक मंडी की तैयारी शुरू, टिकरी खमपुर में 70 एकड़ में बनेगा बाजार

नई दिल्ली। दिल्ली में फलों और सब्जियों की बढ़ती मांग और मौजूदा मंडियों पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए सरकार एक नई थोक मंडी बनाने जा रही है. यह मंडी करीब 70 एकड़ जमीन पर विकसित की जाएगी. अधिकारियों के मुताबिक, इस योजना पर काम शुरू हो चुका है और इसे दोबारा गति दी गई है, ताकि जल्द से जल्द मंडी को चालू किया जा सके. नई फल और सब्जी की थोक मंडी उत्तर-पश्चिम दिल्ली के टिकरी खमपुर इलाके में बनाई जाएगी. इसके लिए जीटी करनाल रोड के पास लगभग 70.62 एकड़ जमीन का अधिग्रहण पहले ही किया जा चुका है.

योजना के तहत इस मंडी को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, ताकि किसानों, व्यापारियों और खरीददारों को सुविधा मिल सके. सूत्रों की माने तो दिल्ली सरकार की यह योजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर आधारित होगी. इसका मतलब यह है कि मंडी के निर्माण और संचालन में सरकारी और निजी कंपनियां मिलकर काम करेंगी. अधिकारियों ने साफ किया है कि इस प्रोजेक्ट से दिल्ली सरकार या दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड पर कोई सीधा आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा. इस परियोजना के लिए DAMB ने एक कंसल्टेंट की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. कंसल्टेंट प्रोजेक्ट की पूरी योजना, डिजाइन और संचालन मॉडल तैयार करेगा. टेंडर दस्तावेजों में कहा गया है कि मंडी का मॉडल ऐसा होगा जिससे यह लंबे समय तक टिकाऊ और लाभकारी बनी रहे. जानकारी के अनुसार, इस नई थोक मंडी के शुरू होने से आजादपुर मंडी पर पड़ने वाला भारी बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा. गौरतलब है कि आजादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी मानी जाती है, जहां रोजाना हजारों टन फल और सब्जियां आती हैं.

लश्कर आतंकी मोहम्मद आरिफ की फांसी पर फिर होगी सुनवाई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2000 में हुए ऐतिहासिक लाल किला हमले के दोषी और मौत की सजा पाए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की उपचारात्मक याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है। बृहस्पतिवार को अदालत ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए आरिफ के पास उपलब्ध अंतिम कानूनी विकल्प पर विचार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है इस हमले में सेना के तीन जवान शहीद हो गए थे। न्यायालय ने इस मामले में सजा के खिलाफ आरिफ की पुनर्विचार याचिका तीन नवंबर 2022 को खारिज कर दी थी। आरिफ उर्फ अशफाक को अक्टूबर 2005 में निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी और दिल्ली उच न्यायालय ने सितंबर 2007 में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद आरिफ ने उच न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए उचतम न्यायालय का रुख किया था। शीर्ष अदालत ने अगस्त 2011 में आरिफ को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा था। बृहस्पतिवार को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की विशेष पीठ ने वकीलों द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर गौर किया।

खालिस्तानियों की चुप्पी क्यों?

विदेशी धरती पर बैठकर खालिस्तानी राग अलापने वाले गुरपतवंत सिंह पन्नू या उनके जैसे अनेक ऐसे लोग हैं जो इस मूवमेंट को चला रहे हैं और अक्सर इनका केन्द्र भारतीय पंजाब पर रहता है जिसे वह खालिस्तान बनाने के ख्वाब स्वयं भी देखते हैं और युवा पीढ़ी को गुमराह कर उन्हें भी ऐसा करने के लिए उकसाते हैं, जबकि असल सच्चाई यह है कि न तो कोई भी भारतीय सिख कभी खालिस्तान का समर्थक रहा है और न हो सकता है क्योंकि भारत का हर नागरिक भले ही वह किसी भी धर्म से सम्बन्ध रखता हो उसके लिए देश पहले है। सिखों ने अगर खालिस्तान लेना होता तो देश के बंटवारे के समय ही जब अंग्रेजी हकूमत ने हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का बंटवारा किया, उसी समय ले लिया होता, मगर नहीं क्योंकि सिख समुदाय का हिन्दू धर्म के लोगों के साथ नाखुन-मांस का रिश्ता है जिसे कोई अलग नहीं कर सकता। दोनों ही समुदाय भले अलग हो मगर इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी रीति-रिवाज एक जैसे ही हैं। यहां एक बात और दिलचस्प है कि आज तक इन खालिस्तानियों के द्वारा पाकिस्तान में जो पंजाब है उसके प्रति कभी कुछ नहीं कहा, जबकि देखा जाए तो पाकिस्तानी पंजाब में इतने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल मौजूद हैं। सिखों का सबसे पवित्र ननकाणा साहिब जहां गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ वह ऐतिहासिक स्थल पाकिस्तान में है। इतना ही नहीं भारतीय पंजाब से कई अधिक ऐतिहासिक तीर्थस्थल पाकिस्तान में हैं जिनमें खालिस्तान समर्थक दिलचस्पी लेते हुए नजर नहीं आते या यह कहा जाए कि उनके प्रति वह कभी रुचि नहीं दिखा सकते, क्योंकि पाकिस्तानी समर्थन के बिना खालिस्तानियों का आंदोलन खत्म हो जाएगा। यह शुरू से ही, पाकिस्तानी समर्थन पर निर्भर रहे हैं। सिनेमा के माध्यम से खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा- पाकिस्तान में यह देखा जा रहा है कि सिनेमा का उपयोग भारत-विरोधी गतिविधियों, विशेष रूप से खालिस्तान से जुड़ी गतिविधियों को तेज करने के एक उपकरण के रूप में लगातार बढ़ रहा है, जो लोग भारत में प्रतिबंधों के कारण खालिस्तान का प्रचार करने वाली फिल्मों या गीत बनाने में कठिनाई महसूस करते है, वह इस स्थिति का पूरा लाभ उठाते दिखाई देते हैं। वह पाकिस्तान जाते हैं, बिना किसी रोक-टोक के अपनी गतिविधियां करते हैं और फिर उस सामग्री को सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। अपनी आंतरिक विफलताओं का सामना करने के बजाय, पाकिस्तानी राज्य लगातार भारत-विरोधी कथानकों पर निर्भर होता जा रहा है। इसी उद्देश्य से राज्य-समर्थित मीडिया हाउसों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और फिल्म निर्माताओं को सक्रिय किया जा रहा है ताकि सांस्कृतिक उत्पादन के माध्यम से ध्यान भटकाया जा सके और जनमत को प्रभावित किया जा सके। किसी भी स्थिति में, सिनेमा का हथियारीकरण कोई नई घटना नहीं है। दशकों से पाकिस्तानी फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में सिख पात्रों, विशेषकर सिख महिलाओं, को अत्यंत संकीर्ण और गहराई से विवादास्पद दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। बेवफ़ाया (1981) जैसी फिल्में इस बात के लिए याद की जाती है कि उनमें एक सिख महिला के भावनात्मक झुकाव को एक मुस्लिम पुरुष नायक की ओर इस तरह दिखाया गया है, जिससे परोक्ष रूप से इस्लाम और मुस्लिम संस्कृति को श्रेष्ठ और अधिक आकर्षक प्रस्तुत किया जाता है। पंजाबन (2003), जो एक पाकिस्तानी मुस्लिम पुरुष और एक भारतीय सिख महिला के बीच सीमा-पार प्रेम कहानी पर केंद्रित है, को भी इस धारणा पर आधारित होने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा कि सिख महिलाएं भावनात्मक या आध्यात्मिक रूप से इस्लाम और मुस्लिम पाकिस्तान की ओर आकर्षित होती हैं। पाकिस्तानी सिनेमा का उपयोग भारत-विरोधी कथानकों को मजबूत करने और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, धार्मिक प्रतीकों के शोषण हेतु किया जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि ऐसी रणनीतियां पवित्र स्थलों की मर्यादा को क्षीण करती हैं, विश्वास के राजनीतिकरण को सामान्य बनाती हैं और कला व धर्म को राज्य सत्ता के उपकरण में बदल देती हैं। इनकी कीमत सरकारें नहीं, बल्कि वे समुदाय चुकाते हैं जिनकी पहचान का बार-बार हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए सभी सिख संगठनों को इस मुद्दे का संज्ञान लेना चाहिए और इसे रोकने के लिए अभियान शुरू करने चाहिए, अन्यथा भविष्य में सिख समुदाय को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दरबार साहिब की मर्यादा किससे भंग हुई? - श्री दरबार साहिब जो कि सिख समुदाय का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है और आज देश ही नहीं विदेश से भी अगर कोई सैलानी भारत आता है तो वह श्री दरबार के दर्शनों के लिए जरूर जाता है। इनमें ज्यादातर श्रद्धालु गैर सिख रहते है जिन्हें सिख मर्यादा की जानकारी नहीं रहती जिसके चलते कई बार मर्यादा भंग होने के अवसर रहते हैं, मगर यह जिम्मेवारी वहां तैनात शिरोमणि कमेटी के सेवादारों की बनती है कि वह आने श्रद्धालुओं खासकर गैर सिखों को मर्यादा के प्रति जागरूक करें, वहीं कुछ शरारती अनसर इसका लाभ उठाकर जानबूझ कर श्री दरबार साहिब की पवित्रता भंग करने की फिराक में रहते है और हैरानी इस बात की है कि वह अक्सर अपने कृत्य को अंजाम देकर निकल जाते है, मगर उनके खिलाफ सेवादारों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जिसका पुख्ता प्रमाण हाल ही में देखने को मिला जब एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने सरोवर में न सिर्फ हाथ-पैर धोए, बल्कि मुंह में हाथ डालकर वहीं पानी बाहर निकालकर कुल्ला भी किया और वीडियो में साफ दिख रहा है कि वह हाथ उठाकर किस प्रकार सिख समाज को चैलेंज करके गया। ऐसा करने में उसे काफी समय लगा होगा मगर क्या इस दौरान किसी सेवादार या संगत का भी उस पर ध्यान नहीं गया। अक्सर देखने में आता है जब किसी महिला के सिर से थोड़ी सी भी चुनरी सरक जाए या फिर सैलानी फोन से अपने या अपने पारिवारिक सदस्यों की फोटो ही क्यों न ले रहे हों तो सेवादारों के साथ-साथ संगत के लोग भी उन्हें तुरन्त रोककर नसीहत देने बैठ जाते है, पर इस मुस्लिम लड़के को न तो रोका गया और न ही आज तक इसके खिलाफ शिरोमणि कमेटी या किसी प्रमाणित सिख जत्थेबंदी ने कोई प्राथमिकी दर्ज करवाई है। वहीं दूसरी ओर 2024 में योग दिवस के मौके पर एक हिन्दू लड़की के योग करने पर खूब हो-हल्ला हुआ। सभी इसे मर्यादा का उल्लंघन बता रहे थे, पर आज इतना सब होने के बाद वह भी चुप्पी साधे हुए हैं जो कई सवालों को जन्म देता है। अजयपाल सिंह बंगा की ट्रंप टीम में उपस्थिति - विश्व बैंक समूह के भारतीय-अमेरिकी अध्यक्ष अजयपाल सिंह बंगा को गाज़ा संघर्ष को समाप्त करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापक योजना के तहत गठित नए 'शांति बोर्ड' में नियुक्त किया गया।

प्रयागराज की गरिमा

प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के स्नान पर ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को स्नान करने से रोकने पर जो बवाल मचा वह प्रयागराज की गरिमा के पूरी तरह से विपरीत है। प्रयागराज को लेकर सभी साधु-संतों और समाज में चिंता भी है और गहरी चिंता भी, क्योंकि प्रयागराज की गरिमा को इस तरह की घटनाओं से ठेस पहुंची। आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थकों को पीटा। शंकराचार्य के रथ को रोका गया। शंकराचार्य ने इसे संतों का अपमान बताते हुए धरने पर बैठने का फैसला किया और इसे धर्म से जुड़ी लड़ाई यानि धर्मयुद्ध घोषित कर दिया। इसी बीच माघ मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजकर उनके शंकराचार्य होने पर सवाल उठा दिए। माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भेजे नोटिस में पूछा है कि उन्होंने अपने नाम के आगे 'शंकराचार्य' क्यों लगाया है? मेला प्राधिकरण के नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन एक मामले का उल्लेख है। मेला प्रशासन का कहना है कि अभी तक इस मामले में कोई आदेश पारित नहीं हुआ है, ऐसे में कोई भी धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक नहीं हो सकता। बावजूद इसके स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला क्षेत्र में लगे शिविर के बोर्ड पर अपने नाम के आगे 'शंकराचार्य' अंकित किया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को उनके गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद शंकराचार्य बनाया गया था। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का 99 साल की आयु में लंबी बीमारी के बाद 11 सितंबर 2022 को निधन हो गया था। उन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के झोतेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में अंतिम सांस ली थी। उनको समाधि देने से पहले ही उनके उत्तराधिकारियों के नाम का ऐलान कर दिया गया था। स्वामी स्वरूपानंद की वसीयत के आधार पर उनके निजी सचिव और शिष्य सुबोद्धानंद महाराज ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ और स्वामी सदानंद को द्वारका शारदा पीठ की गद्दी सौंपी थी। यह घोषणा शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के पार्थिव शरीर के सामने की गई थी। सनातन परंपरा में इन मठों के प्रमुखों को ही शंकराचार्य कहा जाता है। बाद में उन्हें शंकराचार्य बनाए जाने को लेकर विवाद हो गया, क्योंकि संन्यासी अखाड़े ने उन्हें शंकराचार्य मानने से इंकार कर दिया था, तब से मामला सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेला प्रशासन को नोटिस का जवाब देते हुए कहा है कि उनके शंकराचार्य होने को लेकर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने अपने जवाब में पूरी कानूनी प्रक्रिया का ब्यौरा दिया है।

उन्होंने अपने वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा है कि अगर प्रशासन ने नोटिस को 24 घंटे के भीतर वापिस नहीं लिया तो वह कानूनी कार्यवाही करेंगे। इस पूरे विवाद को लेकर संत समाज बंट गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके समर्थकों का कहना है कि सरकार, प्रशासन या भारत के राष्ट्रपति को भी यह अधिकार नहीं है कि वह तय करें कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय संत समाज और शंकराचार्य ही करेंगे। दूसरी तरफ उनको शंकराचार्य स्वीकार नहीं करने वाले संत अपनी अलग भाषा बोल रहे हैं। सवाल यह भी है कि 2025 के महाकुम्भ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य के रूप में मान्यता दी गई थी तब द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती और श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य विधुशेखर भारती और ज्योतिष मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने एक साथ महाकुम्भ में स्नान किया था। माघ मेले के दौरान ऐसा क्या हुआ कि उनको नोटिस भेजकर विवाद को हवा दी गई है। विपक्ष कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि गुरु-शिष्य की एक अखंड परम्परा होती है, जिसके तहत शंकराचार्य चुने जाते हैं लेकिन अब तो शंकराचार्य को कागज देकर यह पूछा जा रहा है कि आप हैं कौन? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कई बार अपनी मुखरता और बयानों के कारण विवादों में रहे हैं। वेदांत, पुराण और ज्योतिष शास्त्र में भी विशेषज्ञता प्राप्त एक विद्वान के रूप में प्रसिद्ध स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर को अधूरा बताते हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से इंकार कर दिया था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के दौरान उन्होंने दर्जनों पुराने मंदिरों को तोड़े जाने का विरोध किया था। उन्होंने गौमांस के निर्यात पर कई बार सरकार से तीखे सवाल भी किए थे। अब ऐसा अचानक क्या हो गया जो उन्हें स्नान करने से भी रोक दिया गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी सनातन का ध्वज लेकर हिन्दुत्व का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। वे गौरक्षा के लिए सक्रिय हैं। उनका दावा है कि 12 सितम्बर, 2022 को उनका पट्टाभिषेक हो चुका है इसलिए कोर्ट का आदेश कोई मायने नहीं रखता। उनकी नियुक्ति वसीयत के मुताबिक हुई है। इस विवाद को लेकर अब जमकर सियासत हो रही है। प्रशासन को इस विवाद को सूझबूझ से सुलझाना चाहिए और उन्हें सम्मानपूर्वक स्नान की अनुमति देनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में संतों के अपमान के लिए कोई जगह नहीं है। धार्मिक आस्था को आघात पहुंचाने की भी कोशिश नहीं होनी चाहिए। इससे धर्म की हानि होती है और लोगों की आस्था खंडित होती है। प्रशासन को शंकराचार्य विवाद में न पड़कर प्रयागराज की गरिमा बहाल करनी चाहिए।

सम्पादकीय...

विजय रथ

फूट में एकता या एकता में फूट? हैरान है! किंतु बृहन मुंबई नगर पालिका (बी.एम.सी.) के चुनाव परिणामों से ऐसा दिखाई देता है। महाराष्ट्र के नगर पालिका चुनाव आने वाले समय में राजनीति का निर्धारण कर सकते हैं। इसके चलते विपक्ष खंडित हो रहा है तथा उसके सहयोगी भी घबरा रहे हैं। यह शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की राकांपा के लिए भी खतरे की घंटी है। इस जीत से मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस का कद बढ़ा है। फडणवीस ने शिवसेना और राकांपा में विभाजन कराया और महा विकास अघाड़ी अर्थात कांग्रेस, ठाकरे शिव सेना और शरद पवार की राकांपा को 2022 में धराशाई किया और 2024 में विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की तथा अब स्थानीय निकायों के चुनावों में भारी जीत दर्ज की है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी को एक नई ऊर्जा मिली है। विपक्ष के लिए महाराष्ट्र एक खोए अवसर के समान है और इससे वह और विखंडित हो गया है। भाजपा के इस विजयी रथ को रोकने के लिए पुराने तौर-तरीके, संरक्षण या विरासत से काम नहीं चलेगा और पवार ने इस बात को समझा है, इसीलिए चुनाव परिणामों के बाद राकांपा के दोनों धड़ों की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि आगामी पंचायत और जिला परिषद चुनावों में दोनों के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन बनेगा। राकांपा को इस जनाधार को बचाना होगा और अजीत पवार तथा शरद पवार के साथ होने से इसमें मदद मिल सकती है किंतु यह मदद भी अल्पकालिक रहेगी। शरद पवार क्षत्रप केन्द्रित राजनीति का प्रबंधन करने में कुशल रहे हैं और उनकी राजनीति सहकारिता के इर्द-गिर्द रही है, किंतु अब स्थिति बदल रही है। अब राज्य में राजनीति और जटिल तथा केन्द्रीयकृत हो गई है। परिवार के प्रति निष्ठा से अब राजनीतिक समर्थन नहीं मिलता। राकांपा को ब्रांड पवार से परे सोचना होगा और अपनी पहचान और प्रभाव को बनाए रखने के लिए नई तरह की राजनीति पर विचार करना होगा। कांग्रेस के लिए और भी मुसीबत है। निःसंदेह 2024 के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, किंतु बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों में उसके खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी में यह आकलन उठने लगी है कि राहुल गांधी का नेतृत्व प्रभावी नहीं है। कांग्रेस इस भ्रम में भी है कि उसने 250 लोकसभा सीटों पर भाजपा से सीधा मुकाबला किया है। इसलिए उसके बिना कोई भी भाजपा विरोधी गुट नहीं बन सकता। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की प्रभावहीनता भाजपा के लिए लाभकारी है और इसके साथ ही किसी भी क्षेत्रीय क्षत्रप द्वारा अखिल भारतीय भूमिका निभाने में विफल रहने से भी भाजपा को मदद मिल रही है क्योंकि अनेक राज्यों में ये क्षत्रप कांग्रेस के साथ मुकाबला कर रहे हैं और कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेता क्षेत्रीय दलों को अपना प्रतिद्वंद्वी मानते हैं न कि भाजपा विरोधी गठबंधन में अपना सहयोगी। क्षेत्रीय दलों के लिए कांग्रेस उपयोगी सहयोगी है किंतु वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि कांग्रेस फिर से उभर कर शक्तिशाली न बने। तेलंगाना और कर्नाटक में वह क्षेत्रीय दलों के विरुद्ध सफल रही है।

शांति का मुखौटा, सत्ता की रणनीति: ट्रंप का वैश्विक विरोधाभास

नोबेल शांति पुरस्कार की उत्कट अभिलाषा में डूबे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का व्यक्तित्व और कार्यशैली वैश्विक राजनीति के लिए एक गहरी विडंबना एवं विरोधाभास बनकर उभरी है। शांति का मसीहा बनने का उनका दावा जितना आकर्षक दिखता है, उतना ही विरोधाभासी उनके कदमों का यथार्थ है। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में वे जहां शांति स्थापित करने का श्रेय लेना चाहते हैं, वहीं उनके निर्णय, वक्तव्य और नीतियां अक्सर युद्ध, अशांति, भय और अस्थिरता को जन्म देती दिखाई देती हैं। यह कैसी शांति है, जो बमों की गूंज, प्रतिबंधों की मार और नफरत की भाषा के साथ चलती है? यह कैसा शांति-दूत होने का नाटक है, जिसमें मानवता का रक्त बहता रहे और सत्ता अपने हित साधती रहे? गाजा में शांति स्थापना के लिए ट्रंप की प्रस्तावित योजना इसी विरोधाभास का नवीन उदाहरण है। इसे शांति से अधिक व्यापारिक सौदे की तरह प्रस्तुत किया गया, मानो दशकों से हिंसा, विस्थापन और अस्मिता के संकट से जूझ रहे लोगों का भविष्य किसी रियल एस्टेट या आर्थिक पैकेज से तय किया जा सकता हो। अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, स्थानीय जनता की सहमति और जवाबदेही-इन सबको दरकिनार कर शांति थोपने की यह कोशिश बताती है कि ट्रंप की दृष्टि में शांति कोई नैतिक या मानवीय मूल्य नहीं, बल्कि शक्ति-प्रदर्शन और राजनीतिक लाभ का औजार है। इस तरह बमों के साये में शांति का दावा ढकोसला ही है, जिसमें शांति का सौदा एवं सत्ता की भूख ही दिखती है। ट्रंप की कथित शांति योजना, शांति के नाम पर वर्चस्व की राजनीति ही है। ऐसा लगता है शब्द अहिंसा के और कर्म हिंसा के है। ट्रंप संयुक्त राष्ट्र को अक्षम, पक्षपाती और नौकरशाही से ग्रस्त बताकर उसकी अवहेलना करते रहे हैं, जबकि सच यह है कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए बहुपक्षीय संस्थाओं का ढांचा अनिवार्य है। शक्तिशाली देशों को जब यह ढांचा अपने अनुकूल नहीं लगता, तो वे उसे कमजोर करने लगते हैं-ट्रंप इसी प्रवृत्ति का मुखर चेहरा हैं। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित नए वैश्विक शांति संस्थान का विचार अपने आप में जितना आकर्षक शब्दों से सुसज्जित है, उतना ही अपने अंतर्विरोधों में उलझा हुआ भी है। शांति स्थापना के नाम पर एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था खड़ी करने की कोशिश, जो संयुक्त राष्ट्र जैसे स्वीकृत बहुपक्षीय ढांचे को दरकिनार करती हो, वस्तुतः शांति से अधिक सत्ता-केंद्रित वर्चस्व की आकांक्षा को उजागर करती है। यह प्रश्न स्वाभाविक है कि जिस नेतृत्व की नीतियों का आधार हथियारों के निर्माण और बिक्री, सैन्य गठबंधनों के विस्तार, युद्ध की धमकियों और आर्थिक दंड के जरिये दुनिया पर दबाव बनाना रहा हो, वह अचानक शांति का नया ठेकेदार कैसे बन सकता है? ट्रंप की राजनीतिक सोच में शांति किसी मानवीय प्रतिबद्धता का नहीं, बल्कि सौदेबाजी, नियंत्रण और लाभ का साधन प्रतीत होती है। इसलिए उनके प्रस्तावित शांति संस्थान की उपयोगिता पर गंभीर संदेह खड़ा होता है। बिना वैधता, जवाबदेही और वैश्विक सहमति के खड़ी की गई कोई भी संस्था शांति का वाहक नहीं बन सकती; वह केवल शक्तिशाली देशों की इच्छाओं को थोपने का उपकरण या जरिया ही बनती है। इस संदर्भ में ट्रंप का यह प्रयास शांति की दिशा में एक ठोस पहल नहीं, बल्कि हिंसा-प्रधान नीतियों पर पर्दा डालने और वैश्विक शासन व्यवस्था पर अपनी पकड़ मजबूत करने का एक और षड्यंत्र एवं कुचेष्टा ही दिखाई देता है। ट्रंप की सोच में शांति का अर्थ संघर्षों का समाधान नहीं, बल्कि उन्हें अपने पक्ष में मोड़ना है। कभी वे संयुक्त राष्ट्र के समानांतर इस तरह की एक कथित शांति-व्यवस्था खड़ी करने की बात करते हैं, तो कभी ईरान पर युद्ध की धमकी देते हैं। एक ओर वे यूरोपीय देशों की तारीफ कर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करते हैं, दूसरी ओर उन्हीं देशों पर व्यापारिक प्रतिबंधों और सैन्य खर्च का दबाव डालते हैं। यह दोहरा आचरण और कथनी और करनी का भेद वैश्विक अस्थिरता को बढ़ाता है। शांति की भाषा बोलते हुए हथियारों की बिक्री, सैन्य गठबंधनों का विस्तार और आर्थिक दंड-ये सब उनकी नीतियों के अभिन्न अंग रहे हैं। परिणामस्वरूप दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां युद्ध की आहटें तेज हैं और मानवता अस्तित्व के मुहाने पर पहुंचती प्रतीत होती है। गाजा संकट के संदर्भ में यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि बिना वैधता, सहमति और जवाबदेही के थोपी गई शांति कभी स्थायी नहीं होती। यदि नागरिकों की सुरक्षा, जीवन की गरिमा और राजनीतिक अधिकारों को नजरअंदाज किया जाए, तो कोई भी समझौता खोखला साबित होगा। ट्रंप का दृष्टिकोण इन मूलभूत सच्चाइयों को अक्सर अनदेखा करता है। आर्थिक वादों को राजनीतिक अधिकारों के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना एक खतरनाक भ्रम है, जो जमीनी वास्तविकताओं के बोझ से ढह जाता है।

शांति तभी टिकाऊ हो सकती है जब उसमें स्थानीय लोगों की वास्तविक आवाज शामिल हो, उनके दुख-दर्द को समझा जाए और न्यायपूर्ण समाधान की दिशा में ईमानदार पहल हो। भारत को गाजा में शांति प्रयासों में शामिल करने का प्रस्ताव भी इसी जटिलता को उजागर करता है। भारत का कूटनीतिक इतिहास बहुपक्षवाद, संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका और द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थन से जुड़ा रहा है। भारत के इस्राइल से अच्छे संबंध हैं, तो अरब देशों में भी उसकी विश्वसनीयता बनी हुई है। लेकिन यदि शांति प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र को दरकिनार करती है, तो यह भारत की स्थापित कूटनीतिक परंपरा के अनुकूल नहीं होगा। भारत ने हमेशा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बजाय स्थिरता और संवाद को प्राथमिकता दी है। ऐसे में ट्रंप-प्रेरित पहल में शामिल होना भारत के लिए भी एक नैतिक और रणनीतिक चुनौती बन सकता है। वास्तव में ट्रंप की नीतियां एक ऐसे विश्व-दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती हैं, जहां शक्ति ही सत्य है और नैतिकता केवल भाषणों तक सीमित है। उनकी बयानबाजी में नफरत और विभाजन की छाया साफ दिखती है। आप्रवासन, नस्ल, धर्म और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर उनकी भाषा ने वैश्विक स्तर पर असहिष्णुता को बढ़ावा दिया। जब विश्व का सबसे शक्तिशाली देश इस तरह का संदेश देता है, तो उसका असर सीमाओं से परे जाता है। युद्ध केवल गोलियों और मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता, वह विचारों और शब्दों से भी लड़ा जाता है और ट्रंप के शब्द अक्सर आग में घी डालने का काम करते रहे हैं। आज दुनिया जिन संकटों से जूझ रही है-यूक्रेन से लेकर मध्य पूर्व तक, एशिया से अफ्रीका तक, उनमें कहीं-न-कहीं महाशक्तियों की स्वार्थपूर्ण नीतियों की छाया है। ट्रंप का दौर इस प्रवृत्ति को और उग्र बनाता दिखाई दिया, जहां वैश्विक सहयोग के बजाय 'मैं पहले' की मानसिकता हावी रही। शांति के नाम पर दबाव, सौदेबाजी और धमकी-यह त्रयी मानवता के लिए घातक है।

जो नेता स्वयं को शांति का प्रतीक बताता है, उससे अपेक्षा होती है कि वह पुल बनाए, दीवारें नहीं; संवाद बढ़ाए, युद्ध नहीं; भरोसा पैदा करे, भय नहीं। इस तरह प्रश्न यही है कि क्या शांति पुरस्कार की आकांक्षा मात्र से कोई शांति-दूत बन सकता है? यदि जवाबदेही, सहमति और मानवीय मूल्यों के बिना शांति थोपने की कोशिश की जाए, तो वह शांति नहीं, एक नया संघर्ष जन्म देती है। ट्रंप की कार्यशैली इसी सच्चाई की गवाही देती है। आज जब मानवता युद्धों में अपने जीवन को खो रही है, तब शांति का ढोंग और भी क्रूर प्रतीत होता है। दुनिया को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो शक्ति के प्रदर्शन से नहीं, बल्कि करुणा, न्याय और बहुपक्षीय सहयोग से शांति की राह प्रशस्त करे। अन्यथा शांति मसीहा होने का यह नाटक इतिहास में एक विफल और खतरनाक प्रयोग के रूप में ही दर्ज होगा।

'बाम्बे' मुम्बई बन गया, सिंगापुर या हांगकांग न बन सका

महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय के चुनाव परिणाम बता गए हैं कि इस समय देश में भाजपा का कोई मुकाबला नहीं है। न वह नेतृत्व किसी के पास है और न ही वह संगठन, और न ही वह पैसा। 2024 के आम चुनाव में भाजपा बहुमत के नीचे आ गई थी, उससे वह उभर चुकी है। एक के बाद एक वह महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार के विधानसभा चुनाव अच्छी तरह जीत गई थी। विपक्ष, विशेष तौर पर राहुल गांधी, 'वोट चोरी' की शिकायत करते रहे, पर कोई सुनता नहीं। लोग समझते हैं कि छोटी-मोटी धांधली तो हो सकती है, पर इतने व्यापक स्तर पर नहीं कि वह चुनाव परिणाम ही उलट दे। महाराष्ट्र के चुनाव से पहले दक्षिण से एक चौंकने वाला परिणाम आया है। दूर केरल में तिरुवनंतपुरम में भाजपा अपना मेयर और डिप्टी मेयर बनाने में सफल रही है। यह क्षेत्र कांग्रेस और वाम दलों की कर्मभूमि रही है। तिरुवनंतपुरम से सांसद भी शशि थरूर है। पास वायनाड से प्रियंका गांधी सांसद है। केरल के स्थानीय चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन संतोषजनक रहा। बताया जाता है कि वहां संघ की 5142 शाखाएं है। इस वैचारिक मेहनत का परिणाम नज़र आने लगा है। विपक्ष को सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि आगे केरल समेत तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम के चुनाव है। महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों की गूंज दूर तक सुनी जाएगी। महाराष्ट्र के 29 में से 25 नगर निगम में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा को 1400 सीटें मिली हैं तो कांग्रेस को 324, यह फासला कांग्रेस कैसे पार करेगी? एक साल पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी झटका मिला था। वह प्रदेश दशकों कांग्रेस का गढ़ रहा और देश का सबसे समृद्ध प्रांत है। 140 साल पहले मुम्बई में कांग्रेस का जन्म हुआ था। यहां ही यह कमजोर पड़ गई है। मुम्बई की महानगरी का 74000 करोड़ रुपए का बजट हिमाचल प्रदेश और गोवा से अधिक है। मुम्बई की शक्ल भी बदल गई है। यह 'मराठी मानुस' का ही शहर नहीं रहा जिस पर कभी बाला साहब ठाकरे का कठोर शासन रहा है। अब वह सबका शहर बनता जा रहा है इसीलिए इस बार 'मराठी अस्मिता' का कार्ड भी नहीं चला। भाजपा को गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का समर्थन अधिक मिला है। राज ठाकरे द्वारा फिर गैर-मराठियों को गाली देने के कारण उद्धव ठाकरे को भी नुकसान पहुंचा है लेकिन बीएमसी के चुनाव परिणाम भी बता गए हैं कि (1) भाजपा अपने बल पर मेयर नहीं बना सकी और उसे शिवसेना शिंदे को साथ लेना पड़ेगा। या और तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। 227 सीटों वाली बीएमसी में भाजपा को 89 सीट ही मिली हैं। अर्थात बहुमत से बहुत नीचे है। (2) अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो जाता तो शायद परिणाम अलग होते। उद्धव ठाकरे की पार्टी को 65 सीटें मिली और वह दूसरे नम्बर पर रही है। केन्द्रीय मुम्बई में उनका प्रभाव अभी कायम है। पर कांग्रेस को तो केवल 24 सीटें ही मिली, पर फिर भी वह 'अपनी शर्तों पर' गठबंधन के लिए ज़िद करते हैं जैसी अब तमिलनाडु में द्रमुक के साथ किया रहा है। वह समझ नहीं रहे कि नीचे से ज़मीन खिसक रही है। बीएमसी के चुनाव में भाजपा का स्ट्राइक रेट 66त्र रहा है, उद्धव ठाकरे की पार्टी का 39त्र,जबकि कांग्रेस का 16त्र। किस गलतफहमी में है यह सज्जन शरद पवार को भी बहुत धक्का पहुंचा है। महा विकास अघाड़ी का भविष्य खतरें में है। पवार जैसे पुराने पावर ब्रोकरेज का समय निकल गया है। नई सोच, नई नीति और नए चेहरे की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। भाजपा का नेतृत्व तो फास्ट ट्रैक पर है, पर विपक्ष पुरानी घिसी-पिटी राजनीति के चक्कर में फंसा हुआ है। यह भी दिलचस्प है कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के एक घटक, शिवसेना शिंदे, ने अपने 29 विजयी पार्षदों को बांद्रा के फाइव स्टार ताज लैंड्स एंड होटल में बुला लिया है। कहा तो जा रहा है कि उनकी ट्रेनिंग होगी, पर घबराहट लगती है कि कहीं भेड़ें खिसक न जाएं। यह हमारी राजनीति का बहुत घिनौना चित्र पेश करती है कि बार-बार जन प्रतिनिधियों को होटलों या रिजोर्ट में बंद करना पड़ता है। घबराहट रहती है कि कहीं उनका कोई शिकार न कर जाए। आजकल राजनीतिक वफ़ादारी बहुत लचीली हो चुकी है। भाजपा को घबराहट नहीं, क्योंकि उनके पास सत्ता भी है, पैसा भी है। यह भी नज़र आने लगा है कि भाजपा धीरे-धीरे सहयोगियों को ही खत्म कर रही है। पहले यह बिहार में देखा गया और अब महाराष्ट्र में देखा जा रहा है। जहां एक उपमुख्यमंत्री अजीत पवार हाशिए पर चले गए हैं तो दूसरे उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपने विजयी पार्षदों को होटल में बंद करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की बल्ले-बल्ले है। उन्हें अभी से 2029 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के सम्भावित उम्मीदवार की चर्चा शुरू हो गई है। अगली पीढ़ी से है। महाराष्ट्र जैसे साधन सम्पन्न प्रदेश के मालिक है। अब मुम्बई पर भी उनका कब्ज़ा हो गया है। पर इसी में उनके लिए खतरा भी लिखा हुआ है। कई लोग उन्हें ठोकर मारने के लिए तैयार होंगे। मुम्बई की राजनीति उसका केवल एक पक्ष है। असली बात तो यह है कि हमारे सबसे धधकते शहर की हालत कब सुधरेगी? केन्द्र का ध्यान अहमदाबाद पर अधिक लगता है। वर्तमान चुनावों से पहले महाराष्ट्र के प्रमुख नगर निगमों, जिन में मुम्बई भी शामिल है, में चुनाव फरवरी 2017 में हुए थे। देश का सबसे समृद्ध शहर इतने सालों से जन प्रतिनिधि के बिना चल रहा है। इस बीच मुम्बई का पतन होता रहा। किसी ने सही कहा है कि मुम्बई का बजट 74000 करोड़ रुपए का है, पर यहां सड़कों पर 74000 गड्ढे भी हैं ! इसकी जनसंख्या 1.25 करोड़ है। यह देश का सबसे महंगा शहरी भूगोल है! एक हिस्सा तो बहुत चमकता है जिस में बड़े-बड़े उद्योगपति, बिसनेसमैन और विमेन, बालीवुड के फिल्म स्टार, क्रिकेट के खिलाड़ी और दूसरे रईस रहते हैं जिनकी तस्वीरें हम सोशल मीडिया में देखते रहते हैं। पैसे का खुला अश्लील प्रदर्शन होता है। देश का सबसे महंगा घर, मुकेश अंबानी का 27 मंजिला 'एंटिलिया' मुम्बई में है, पर एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी भी मुम्बई में ही है। धारावी सिर्फ 2.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस छोटे से क्षेत्र में 10 लाख लोग रहते हैं जहां न पीने के पानी का उचित प्रबंध है, न पर्याप्त शौचालय ही है। अधिकतर लोग ऐसी कोठरियों में रहने को मजबूर हैं जहां न रोशनी है, न हवा है, पर मजबूरी है। जो बाहर से रोजगार की तलाश में मुम्बई आता है उसे पैर रखने की जगह भी तलाशनी पड़ती है। पर धारावी में धंधा भी चलता है और अनुमान है कि यहां का उद्यमशील छोटा उद्योग वार्षिक 1 अरब डालर का सामान तैयार करता है। इसे 'मिनी इंडिया' भी कहा जाता है जो हर तरह की समस्या के बावजूद आगे बढ़ रहा है, पर ऐसे स्लम देश पर कलंक है। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के सबसे समृद्ध शहर में लाखों लोग पशुओं की तरह रहने पर मजबूर हैं। हर बरसात में शहर डूब जाता है। ट्रेन सर्विस जो लाइफलाइन है ठप्प हो जाती है। अब तो दिल्ली स्टाइल प्रदूषण की शिकायत हो रही है। किसी भी शहर से ज्यादा मुम्बई का देश के प्रति योगदान है। इसने देश को सबसे अधिक राजस्व दिया है। किसी भी शहर ने इतना आतंकी प्रहार बर्दाश्त नहीं किया जितना मुम्बई ने किया है, पर किसी भी शहर ने अपने दरवाज़े मज़लूमों के लिए इस प्रकार नहीं खोलकर रखे जैसे मुम्बई ने खोल रखे हैं। हम तो इसे सिंगापुर, हांगकांग और दुबई के बराबर का शहर बनाना चाहते थे। धन के मामले में शहर बराबरी कर रहा है, पर नागरिक सुविधा तो तीसरी दुनिया की है। क्या यह चुनाव परिणाम कुछ बदलेंगे? आखिर अब ट्रिपल इंजन सरकार होगी, पर सम्भावना बहुत कम है। समस्या इतनी विशाल है कि इलाज नज़र नहीं आता। इस 'सपनों के शहर' में लोग रोज़गार के लिए धड़ाधड़ आ रहे हैं, पर जगह कहां है? इसीलिए तो धारावी जैसी काल कोठरियों में रहना पड़ता है। चुनाव अभियान के दौरान जिन मुद्दों को उछाला गया उनमें यह बिलकुल गायब थे जो लोगों की रोज़मर्रा ज़िन्दगी से जुड़े हैं। अधिक ज़ोर रेवड़ियां देने पर लगा रहा जिनसे अस्थाई राहत ही मिलती है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शर्मा ने कदम ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैसफिक एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शर्मा, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादस्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/78882)

राष्ट्रीय राजमार्ग सख्या-927 के चौडीकरण/ निर्माण के भू-अधिग्रहण दावों की हुई सुनवाई

बहराइच।

बाराबंकी-बहराइच सेक्शन होगा फोरलेन

जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट/सक्षम प्राधिकारी भूमि अध्यापित बहराइच राजेश प्रसाद द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सख्या-927 (बाराबंकी-बहराइच सेक्शन) के फोरलेन चौडीकरण/निर्माण के भू-अधिग्रहण हेतु ग्राम-मुस्तफाबाद, आदमपुर, तप्पेसिपाह, रिठौडा व झुकिया की अर्जित की जाने वाली भूमि का मुआवजा निर्धारित किये जाने से पूर्व प्रभावित कृषकों से प्राप्त हुए दावों के सम्बन्ध में कपूरथला परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में सुनवाई की गई। दावों की सुनवाई के दौरान उपस्थित कृषकों में से कुल 8 कृषकों अतुल सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह, आशीष कुमार यादव पुत्र राम सरन यादव, मो. अजहरूद्दीन, मो. अफजाल, मो. सुजाउद्दीन मो. अबुजर पुत्रगण कमालुद्दीन, दीपचन्द पुत्र रामआसरे, मो. रूमान उर्फ मो. सिबली पुत्र फसी अहमद, मो. अलीम अंसारी पुत्र मो. शब्बीर, रामावती पत्नी हरिद्वार व राममुझ पुत्र दुबर द्वारा अलग-अलग 08 दावा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है। सुनवाई में उपस्थित कृषकों को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अध्यासि) श्री प्रसाद द्वारा आश्वस्त किया गया कि प्रस्तुत दावा पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रभावित भूमि का मुआवजा नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि प्रभावित भू-स्वामियों को समय से भुगतान सुनिश्चित किया जाये तथा इस प्रक्रिया में प्रभावित होने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा कृषकों को यह भी आश्वस्त किया गया कि प्रभावित क्षेत्रफल में जो परिसम्पत्तियां प्रभावित होंगी उसका भी प्रतिकर भूमि के प्रतिकर के साथ भुगतान किया जायेगा। उन्होंने कहा कि अर्जन प्रभावित व्यक्ति अपने भूमि के सम्बन्ध में समस्याओं से कभी भी अवगत करा सकते है।

वक्फ कब्रिस्तान पर अवैध रूप से लगाया जा रहा सबमर्सिबल

फतेहपुर।

कब्र से मिट्टी व हड्डियों को रातोंरात हटाकर किया गया गड्ढा
पीड़ित ने पालिका ईओ से लगाई न्याय की गुहार

नगर पालिका परिषद फतेहपुर के पीछे स्थित वक्फ कब्रिस्तान पर अवैध रूप से लगाये जा रहे सबमर्सिबल को लेकर फहीम अहमद ने पालिका ईओ को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित फहीम अहमद पुत्र अब्दुल खालिक निवासी इमामगंज, फतेहपुर ने बताया कि उक्त कब्रिस्तान में कब्र को खोद कर ही सबमर्सिबल का बोर किया जा रहा है। कब्र से निकली मिट्टी व हड्डियों को रातों रात हटाकर गड्ढा किया गया है। बाउन्ड्रीवाल को भी गिरा दिया गया है। पीड़ित ने बताया कि उसका अनुमान है कि सबमर्सिबल पालिका द्वारा ही लगवाया जा रहा है, जबकि सम्बन्धित लोगों की नजर कब्रिस्तान की कीमती जमीन पर है। पीड़ित ने बताया कि नगर पालिका परिषद फतेहपुर के अधिशाषी अधिकारी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। ईओ ने जाँच कराने का आश्वासन दिया है।

एसआईआर कार्यो के लिए भाजपाईयों ने कसी कमर

मुरादाबाद।

एसआईआर से संबंधित विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी देहात विधानसभा के दीनदयाल नगर शक्तिकेंद्र अम्बेडकर स्कूल शक्तिकेंद्र की बैठक आयोजित भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला के निर्देशानुसार एसआईआर से संबंधित विषयों को लेकर रामगंगा विहार मंडल के सैक्टर युवा केंद्र बिल्डिंग दीनदयाल नगर शक्तिकेंद्र एवं नया गांव अम्बेडकर स्कूल शक्तिकेंद्र की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में वक्ताओं में महानगर महामंत्री दिनेश शीर्षवाल पूर्व महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, देहात विधानसभा प्रवासी राजीव गुप्ता शक्तिकेंद्र संयोजक निर्वेश भटनागर ने नए वोट बनवाने को लेकर विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला एवं अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य वक्ता दिनेश शीर्षवाल ने कहा कि नवमतदाता बनवाने को सैक्टर संयोजक,बीएलए - 2 बूथ अध्यक्ष अपनी टीम को साथ लेकर घर घर संपर्क करना है । पूर्व महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा ने कहा कि वोटर फॉर्म वितरित कर जरूरी प्रपत्र लेकर वोट बनवाने हैं । देहात विधानसभा शक्तिकेंद्र प्रवासी राजीव गुप्ता ने कहा कि पूर्व में बने मतदाताओं के वोटर सूची में अवलोकन करना है 25 जनवरी को नवमतदाता महाअभियान का दिन है सभी शक्ति केंद्रों के बूथ पर बीएलओ उपस्थित रहेंगे। बैठक में महानगर महामंत्री दिनेश शीर्षवाल, पूर्व महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा,देहात विधानसभा शक्तिकेंद्र प्रवासी राजीव गुप्ता,पार्षद पंकज शर्मा, महानगर मंत्री शशी किरण, सैक्टर संयोजक निर्वेश भटनागर, सैक्टर संयोजक संजीव शर्मा, मंडल महामंत्री मयंक कश्यप, अनुज शर्मा,मंडल उपाध्यक्ष विजय वर्मा,ओ पी चौधरी,अनूप महरोत्रा,राजीव गुप्ता, अमित कुमार,कामेश गुप्ता,आशीष सक्सैना आदि उपस्थित रहे ।

रंगारंग प्रस्तुतियों के बीच हुआ साहित्योत्सव-2026 का शुभारंभ

मुरादाबाद।

जनपद में उदीषा चौपाला साहित्योत्सव-2026 का गुरुवार को शुभारंभ हो गया। दीप प्र'ज्वलित करके फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने इस 5 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ किया। आशुतोष राणा ने अपने संबोधन में कहा कि, पशु और पशुपति में सिर्फ साहित्य, संगीत और कला का अंतर होता है। यही तीनों चीजें हैं जो पशु को पशुपति बनाती हैं। उन्होंने कहा, मुरादाबाद आज संपत्ति के लिए पहचाना जाता है। लेकिन मुरादाबाद का इतिहास देखें तो इस धरती ने जिगर मुरादाबादी जैसे महान साहित्यकार दिए हैं। आशुतोष राणा ने कहा कि आज इस साहित्योत्सव के आगाज से साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में मुरादाबाद सिर्फ संपत्ति के लिए नहीं बल्कि साहित्य के लिए भी याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी साहित्य की रुचि वाले हों तो उस क्षेत्र का कल्याण होता है और अपूर्व विकास होता है। बता दें कि मुरादाबाद के कमिश्नर आन्जनेय सिंह की पहल उदीषा साहित्योत्सव-2026 का आयोजन 22 से 26 जनवरी तक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉ. कुमार विश्वास, सुखविंदर, मनोज तिवारी, सोना महापात्रा, चेतन भगत, गुलशन ग्रोवर, ऋचा अनिरुद्ध, आशुतोष राणा, वसीम बरेलवी, नवाज देवबंदी, अनुषा रिजवी, पंडित साजन मिश्र, गगन गिल, अक्षत गुप्ता, सुनंदा शर्मा और नियाजी ब्रदर्स हिस्सा लेंगे। मुरादाबाद में दिल्ली रोड पर सर्किट हाउस के पीछे मैदान पर आयोजित किए जा रहे इस साहित्योत्सव में 40 से अधिक साहित्यक गोष्ठियां होंगी। इसके अलावा पुस्तक मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 50 से अधिक प्रकाशक शामिल होंगे। इस साहित्योत्सव में कला एवं फोटो दीर्घाओं का भी आयोजन किया गया है। इसी परिसर में पारसी थिएटर, डाकू सुल्ताना की नौटंकी, रामलीला, दस्तानगोई, कव्वाली, लोकनृत्य, हस्तशिल्प, रेत कला, रचनात्मक कार्यशालाएं, सांस्कृतिक संध्याएं, बाल मनोरंजन क्षेत्र, बिदेसिया और फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया है। साहित्योत्सव में मण्डलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. शैफाली सिंह चौहान, शहर विधायक रितेश कुमार गुप्ता, कुन्दरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह, एमएलसी डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त, जीजेयू के कुलपति प्रो. सचिन माहेश्वरी, महापौर विनोद अग्रवाल, डीआईजी मुनिराज, जिलाधिकारी अनुज सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल, नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल, श्रीमती बाल सुन्दरी तिवारी, उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अनुभव सिंह, विशेष मेहमान फिल्मी कलाकार एवं साहित्य प्रेमी आशुतोष राणा, भाजपा जिलाध्यक्ष आकाश पाल, महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला, सुश्री श्वेता जैन, मेजर राजीव ढल, डॉ. महेश दिवाकर, डॉसुमेधा चोटीपुरा, वरिष्ठ भाजपा नेता शिबली चौधरी, विवेक ठाकुर स्कॉलर्स डेन, प्रो. आनन्द कुमार सिंह, प्रो. सत्यव्रत सिंह रावत, यासिर अली स्कॉलर्स डेन, अपर आयुक्त प्रशासन अरूण कुमार, आबिद हुसैन ठेकेदार रामपुर, डॉ. विशेष गुप्ता, राजेश रस्तौगी, विधान परिषद सदस्य सत्यपाल सिंह सैनी एडवोकेट, जिला सूचना अधिकारी सुमित भारती, श्रीमती प्रिया अग्रवाल, रामजी गुप्ता, योगेन्द्र वर्मा व्योम, आवरण अग्रवाल श्रेष्ठ, अपर नगर आयुक्त अतुल यादव, आशुतोष राय, अजीत कुमार सिंह, सुखविंदर सिंह, जयप्रकाश सक्सेना अन्जुम शर्मा, एडीएम सिटी 'ज्योति सिंह आदि उपस्थित रहे।

सपाईयों ने जनेश्वर मिश्र की शख्सियतों पर डाली रोशनी

मुरादाबाद।

पुण्य तिथि पर आयोजित हुई गोष्ठियां

प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक और दार्शनिक जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर सपा के महानगर एवं जिला कार्यालयों पर गोष्ठियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने जनेश्वर मिश्र की शख्सियत पर रोशनी डाली और उनके आदर्शों पर चलने का निर्णय लिया गया।

मकबरा स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। समाजवादी चिंतक जनेश्वर मिश्र को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सपा महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ स्वर्गीय मिश्र के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। विचार गोष्ठी में महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी ने जनेश्वर मिश्र के विचारों को साझा करते हुए कहा कि उनका सपना था कि समाज के हर व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा निःशुल्क मिले। इकबाल हुसैन अंसारी ने कार्यकर्ताओ से उनकेआदर्शों पर चलने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कमरु'जमा सैफी ने कहा कि जनेश्वर मिश्र जी ने समाजवादी विचारधारा और जनता के हितों के लिए पूरे जीवन संघर्ष किया। उन्होंने युवाओं, किसानों और मजदूरों को आंदोलन की नई राह दिखाई। उनके संघर्ष और विचारों को अपनाकर समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा।कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी संचालन महानगर महासचिव गजेंद्र सिंह यादव ने किया।

कार्यक्रम में इकबाल हुसैन अंसारी,सलीम वारसी नगर विधानसभा अध्यक्ष ने कमरु'जमा सैफी, मोहित राघव,राशिद हुसैन अंसारी, पूर्व पार्षद मौअ'जम अली, पूर्व पार्षद शाकिर हुसैन , पूर्व पार्षद डॉ0हसन सलमानी, पूर्व पार्षद नसीम परवेज, पूर्व पार्षद हाजी भूरे अंसारी,फईम मंसूरी, दाऊद अंसारी,आसिफ अंसारी,गुलशन बाबा,अकरम अंसारी,शाहिद पहलवान,आलम शमशाद हुसैन अंसारी, हाजी फईम नितिन,अतुल कुमार दिलदार हुसैन, क़ासिम सलमानी, आदि लोग रहे। समाजवादी विचारधारा के प्रखर स्तंभ और 'छोटे लोहिया' के नाम से विख्यात जनेश्वर मिश्र की आज पुण्यतिथि पर सिविल लाइन्स स्थित पार्टी कार्यालय पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने जनेश्वर मिश्र के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जनेश्वर मिश्र ने अपना पूरा जीवन समाजवाद, लोकतंत्र और शोषित-वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। वे सादगी, ईमानदारी और सिद्धांतों की राजनीति के प्रतीक थे।

7 करोड़ 20 लाख से बनी 3 सड़कों का हुआ शिलान्यास

मुरादाबाद। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, आज एमएलसी डॉ जयपाल व्यस्त एवं कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने मूंढापांडे ब्लॉक के ग्राम जगरामपुरा से 7 करोड़ 20 लाख की लागत से बनने जा रही × सड़को का भूमि पूजन कर किया शिलान्यास किया। जिसमें हनुमान मूर्ति जगरामपुरा से शिव मंदिर गुरुद्वारा होते हुए अहरौला तक संपर्क मार्ग निर्माण लम्बाई 2.700 किमी लागत 424.44 लाख , नगला जटनी से रामगंगा पुल जैतबाड़ा मार्ग तक संपर्क मार्ग निर्माण लम्बाई 1.725 किमी लागत 162.58 लाख और गणेशघाट से हिरनखेड़ा मुस्तकम तक संपर्क मार्ग निर्माण लम्बाई 1.500 किमी लागत 1××.18 लाख शामिल रहे। हनुमान मूर्ति जगरामपुरा से शिव मंदिर गुरुद्वारा होते हुए अहरौला तक बनने वाली सड़क का नाम निर्यातक स्वर्गीय ओमवीर सिंह मार्ग रखा जायेगा। विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने क्षेत्रवासियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सड़क बनने से गांवो की तस्वीर बदल जाएगी, जिससे आवागमन सुगम होगा। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच भी आसान हो जाएगी। गांवों का विकास ही प्रदेश और देश के विकास की मजबूत नींव है। उन्होंने जोर दिया कि उनकी पहली प्राथमिकता गांवों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है, ताकि ग्रामीणों को शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। विधायक ने आश्वासन दिया कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए वह हर संभव प्रयास करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह नई सड़क गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ेगी, जिससे किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी और विद्यार्थियों व मरीजों को भी आने-जाने में परेशानी नहीं होगी। जगरामपुरा अहरौला संपर्क मांग सही नहीं होने से दोनों गांव के लोगों को मंदिर और गुरुद्वारे जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कीचड़ से गुजरते हुए धार्मिक स्थलों पर जाना पड़ता था। अब जल्दी ही सड़क बनने के बाद ईश्वर की आराधना के लिए स्व'छ वातावण मिलेगा। इस अवसर पर निर्यातक ठा.प्रेमवीर सिंह, रामेन्द्र सिंह(दद्दु), निर्यातक राहुल सिंह, ठा.देवेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष नीरज चंद्रा, मंडल अध्यक्ष महेंद्र सैनी, राजेश रस्तोगी, सरदार गुरप्रीत सिंह, सोनू रस्तोगी, रोहित सिंह सहित सैकड़ो क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

28 जनवरी को पेश होगा एमसीडी का बजट, स्थायी समिति की बैठक

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में आज जनहित से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। अध्यक्ष सत्या शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आगामी बजट, विकास कार्यों और टोल टैक्स जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, जो सीधे तौर पर राजधानी के नागरिकों से जुड़े हैं। स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नागरिकों की सुविधाओं और शहर के समग्र विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक के दौरान विकास कार्यों को गति देने और स्थानीय समस्याओं के समाधान पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में सत्या शर्मा ने जानकारी दी कि दिल्ली नगर निगम का जनहितकारी बजट 28 जनवरी 2026 को निगम सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बजट नागरिकों की जरूरतों और शहर की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह बजट दिल्ली के विकास और नागरिक सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। स्थायी समिति अध्यक्षा ने बताया कि स्थायी समिति की विशेष बजट बैठकों में पार्षदों द्वारा दिए गए सुझावों और जमीनी सुझावों को बजट में गंभीरता से शामिल किया गया है। दिल्ली और शहर की मौजूदा स्थिति का समग्र आकलन कर बजट को अंतिम रूप दिया गया है, ताकि इसका लाभ सीधे जनता तक पहुंचे। यह दर्शाता है कि बजट जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अध्यक्षा ने कहा कि पार्षदों को अपने-अपने क्षेत्रों में सड़क, नाली, पार्क, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य विकास कार्यों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इससे स्थानीय स्तर पर समस्याओं का त्वरित समाधान संभव हो सकेगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी। यह निर्णय वार्ड स्तर पर विकास को बढ़ावा देगा। बैठक में टोल टैक्स के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सत्या शर्मा ने स्पष्ट किया कि इस मामले में अधिकारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में निगम का पक्ष मजबूती से रखा जाएगा। इसके लिए सभी पार्षदों और अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक बुलाने की भी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि विशेष बैठक में सभी अहम बिंदुओं पर समन्वय के साथ चर्चा की जाएगी, ताकि सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी और तथ्यपरक पक्ष प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि टोल बंद होने की स्थिति में निगम के राजस्व व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों पर असर पड़ सकता है। एमसीडी के लिए टोल टैक्स राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, यदि यह बंद होता है, तो निगम की वित्तीय स्थिति प्रभावित होगी और विकास कार्यों पर असर पड़ सकता है। इसलिए निगम इस मुद्दे पर अपना पक्ष मजबूती से रखने की पूरी तैयारी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैफिक प्रवाह बेहतर बनाने और प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से कुछ टोल प्लाजा अस्थायी रूप से बंद करने, स्थानांतरण करने अथवा राजस्व साझा करने जैसे विकल्पों पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। निगम इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संतुलित समाधान की दिशा में काम करेगा। एमसीडी का प्रयास है कि ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या का समाधान करते हुए राजस्व को भी नुकसान न हो। इसके लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। निगम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करते हुए एक व्यावहारिक समाधान निकालने का प्रयास करेगा। बैठक में पार्षदों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जनहित से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

जम्मू-कश्मीर में सेना का वाहन खाई में गिरा, 10 जवानों की मौत

श्रीनगर।

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले से एक बहुत ही दुखद समाचार सामने आया है। बृहस्पतिवार को भारतीय सेना का एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। इस भीषण दुर्घटना में 10 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 9 अन्य जवान घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह हादसा भद्रवाह-चंबा अंतरराज्यीय मार्ग पर खन्नी टॉप के पास हुआ। सेना का वाहन नियमित आवाजाही के दौरान पहाड़ी रास्ते पर अचानक सड़क से फिसल गया और सीधे गहरी खाई में जा गिरा।

सेना के वाहन में कुल 17 जवान सवार थे

अधिकारियों ने बताया कि बुलेट-प्रूफ सेना का वाहन, जिसमें कुल 17 जवान सवार थे, एक ऊंची पोस्ट की ओर जा रहा था, तभी ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और वाहन 200 फुट गहरी खाई में गिर गया। सेना और पुलिस द्वारा तुरंत एक संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया गया और अधिकारियों ने बताया कि चार जवानों के शव मिले।

नौ जवानों को घायल हालत में बचाया गया

उन्होंने बताया कि नौ अन्य जवानों को घायल हालत में बचाया गया और उनमें से तीन, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं, उन्हें विशेष इलाज के

अधिकारियों के अनुसार, यह हादसा भद्रवाह-चंबा अंतरराज्यीय मार्ग पर खन्नी टॉप के पास हुआ

लिए उधमपुर सैन्य अस्पताल में एयरलिफ्ट किया गया।

एलजी मनोज सिन्हा ने गहरी संवेदना व्यक्त की

एलजी मनोज सिन्हा ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, "डोडा में एक दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में हमारे 10 बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान जाने से गहरा दुख हुआ। हम अपने बहादुर सैनिकों की उत्कृष्ट सेवा और सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखेंगे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। उन्होंने आगे कहा, इस गहरे दुख की घड़ी में, पूरा देश शोक संतप्त परिवारों के साथ एकजुटता और समर्थन में खड़ा है। 10 घायल जवानों को अस्पताल में एयरलिफ्ट किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों को सर्वोत्तम संभव इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। दुर्गम क्षेत्रों में देश की रक्षा में तैनात इन वीर जवानों की शहादत पर पूरा देश शोक व्यक्त कर रहा है। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, खराब मौसम या फिसलन भरे रास्ते को हादसे का कारण माना जा रहा है।

संत का स्वाभिमान उसका राष्ट्र - सीएम योगी

शंकराचार्य विवाद पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

सोनीपत (हरियाणा)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को हरियाणा के सोनीपत के मुरथल के नागे बाबा मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली सहित बीजेपी के कई सीनियर नेता मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती परंपरागत पालकी यात्रा के दौरान विवाद और धरने पर बैठने को लेकर बिना नाम लिए ही जमकर हमला बोला।

संत की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती

उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा, 'एक योगी, एक संत के लिए, एक सन्यासी के लिए धर्म व राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता, उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती। धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है और राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान होता है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे बहुत कालनेमि होंगे, जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे, हमें उनसे सतर्क रहना होगा। भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रयागराज की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है।

धरने पर बैठे हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती

गौरतलब है कि बीते दिनों माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती परंपरागत पालकी यात्रा के माध्यम से संगम स्नान के लिए जा रहे थे। आरोप है कि प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए उनकी पालकी यात्रा को बीच रास्ते में रोक दिया और उन्हें जिस स्थान पर उतारा गया, वहीं छोड़ दिया गया। इस घटना के विरोध में शंकराचार्य कथित तौर पर उसी स्थान पर धरने पर बैठ गए। वहीं शंकराचार्य ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप भी लगाया है।

मनरेगा को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा- गरीबों से काम का अधिकार छीनना चाहती है भाजपा

नई दिल्ली ।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर निशाना साधा है। मनरेगा बचाओ मोर्चा अभियान में उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत गरीब लोगों को काम करने का अधिकार मिला था, लेकिन अब भाजपा इस योजना को खत्म करना चाहती है। राहुल गांधी ने मनरेगा के मुद्दे पर सरकार की तुलना कृषि कानूनों से की। उन्होंने कहा कि सरकार मजदूरों के साथ वही करना चाहती है, जो उसने तीन काले कृषि कानूनों के जरिए किसानों के साथ किया था। उन्होंने कहा कुछ साल पहले भाजपा ने किसानों पर आक्रमण किया था, लेकिन किसानों और हम सबने नरेंद्र मोदी पर दबाव डाल कर उसे रोक दिया। अब उसी तरह का हमला मजदूरों पर करने की कोशिश हो रही है। राहुल ने

उन्होंने कहा कि सरकार मजदूरों के साथ वही करना चाहती है, जो उसने तीन काले कृषि कानूनों के जरिए किसानों के साथ किया था। उन्होंने कहा कुछ साल पहले भाजपा ने किसानों पर आक्रमण किया था, लेकिन किसानों और हम सबने नरेंद्र मोदी पर दबाव डाल कर उसे रोक दिया।

कहा भाजपा एक ऐसा भारत बनाना चाहती है, जहां सिर्फ एक राजा ही सब कुछ तय करे।

राहुल गांधी ने किया दावा

दिल्ली की केंद्र सरकार निर्णय लेगी कि किस राज्य को कितना पैसा भेजा जाएगा। भाजपा शासित राज्य में ज्यादा पैसा जाएगा और विपक्ष शासित राज्य में कम पैसा जाएगा। केंद्र सरकार ही तय करेगी कि कब कहां काम होगा, किसको कितनी मजदूरी मिलेगी। जो अधिकार मजदूरों को मिलते थे, अब वह ठेकेदारों को मिलेंगे। भाजपा की विचारधारा है कि देश का धन, संपत्ति चुने हुए हाथों में हो और वही लोग इस देश को चलाएं। भाजपा चाहती है कि देश का पूरा धन अमीरों के हाथ में चला जाए, ताकि गरीब, दलित और आदिवासी लोग उनपर निर्भर हो जाएं और उनकी बात मानें।

राहुल बोले भाजपा डरपोक

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा कि भाजपा चाहती है कि देश से लोकतंत्र, संविधान और एक व्यक्ति-एक वोट का अवधारणा खत्म हो जाए। ये लोग आजादी से पहले वाला हिंदुस्तान फिर से लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा भाजपा वाले डरपोक लोग है, इन्हें रोकने के लिए हमें एक साथ खड़ा होना होगा। जिस दिन हम सभी साथ आ गए, उस दिन नरेंद्र मोदी को पीछे हटना पड़ेगा और मनरेगा फिर से बहाल हो

छत्तीसगढ़ की स्टील फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 6 मजदूरों की मौत, 10 से अधिक घायल

छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले से एक भीषण औद्योगिक हादसे की खबर सामने आई है। यहां एक स्टील फैक्ट्री की चालू यूनिट में हुए जोरदार धमाके में कम से कम 6 श्रमिकों की मौत की आशंका है, जबकि 10 से अधिक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है और राज्य में औद्योगिक सुरक्षा मानकों पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह धमाका बकुलाही स्थित रियल इस्पात स्टील प्लांट में हुआ, जब एक कोयला भट्ठी में अचानक धमाका हो गया और घटना के समय मजदूरों का एक ग्रुप भट्ठी के आसपास सफाई का काम कर रहा था। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाके के बाद गर्म कोयले और आग की लपटों के सीधे संपर्क में आने से पीड़ितों को जानलेवा जलने की चोटें आईं।

आज नई चार ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी

केरल ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को केरल का दौरा करेंगे। वे वहां नवाचार और उद्यमिता केंद्र की नींव रखेंगे। इसके साथ ही राज्य में चार नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च करेंगे, जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वित्तीय समावेशन के अगले चरण का प्रतीक है। इसके साथ ही राज्य की राजधानी में एक आधुनिक सकर्सर का उद्घाटन करेंगे। रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, मोदी चार नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे, जिनमें तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इससे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच लंबी दूरी और क्षेत्रीय

संपर्क में सुधार होगा। नई ट्रेन सेवाओं से यात्रियों के लिए यात्रा अधिक किफायती, सुरक्षित और समयबद्ध हो जाएगी और पूरे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार, शिक्षा, रोजगार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को मजबूत प्रोत्साहन मिलेगा। पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड, जो यूपीआई से जुड़ा हुआ और ब्याज मुक्त रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा है, तत्काल तरलता प्रदान करेगा, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देगा।

स्ट्रीट वेंडरों सहित एक लाख लाभार्थियों को लोन वितरित करेंगे

मोदी केरल के स्ट्रीट वेंडरों सहित एक लाख लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि ऋण भी वितरित करेंगे। विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में, मोदी तिरुवनंतपुरम में सीएसआईआर-एनआईआईएसटी इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप हब की आधारशिला रखेंगे। यह केंद्र जीवन विज्ञान और जैव-अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करेगा, आयुर्वेद जैसी पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी, टिकाऊ पैकेजिंग और हरित हाइड्रोजन के साथ एकीकृत करेगा, और स्टार्टअप निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देगा। यह अनुसंधान को बाजार के लिए तैयार समाधानों और उद्यमों में परिवर्तित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। मोदी तिरुवनंतपुरम के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में अत्याधुनिक रेडियोसर्जरी सेंटर की आधारशिला भी रखेंगे। यह सुविधा जटिल मस्तिष्क विकारों के लिए अत्यधिक सटीक, न्यूनतम आक्रामक उपचार प्रदान करेगी, जिससे क्षेत्रीय तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल क्षमताओं में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम में नए पूजपुरा हेड पोस्ट ऑफिस का भी उद्घाटन करेंगे। यह आधुनिक, प्रौद्योगिकी से लैस सुविधा डाक, बैंकिंग, बीमा और डिजिटल सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करेगी, जिससे नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को और अधिक मजबूती मिलेगी।

'शंकराचार्य का अपमान, नही सहेगा हिंदुस्तान..., स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में सपा ने लगाए पोस्टर

लखनऊ ।

प्रयागराज माघ मेले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पालकी रोके जाने को लेकर घटित घटना के विरोध में समाजवादी पार्टी (सपा) मैदान में उतर आई है। पार्टी कार्यालय के बाहर अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में समाजवादी छात्रसभा के पूर्व प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह ने पोस्टर लगाया है। पोस्टर पर 'शंकराचार्य का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान लिख कर समर्थन दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर है।

भाजपा को घेरने के लिए अखिलेश यादव कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। अभी दो दिन पहले ही फोन पर शंकराचार्य से बात कर उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात कही गई थी। इसी क्रम में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने शंकराचार्य से प्रयागराज माघ मेले में मुलाकात की थी।

अखिलेश यादव ने साधा निशाना

एक दिन पूर्व अखिलेश यादव ने बयान जारी कर कहा था कि यदि कोई अधिकारी शंकराचार्य से परिचय और प्रमाण-पत्र मांग रहा है, तो सनातन धर्म का इससे बड़ा अपमान कोई और नहीं हो सकता है। भाजपा सरकार ने सनातन धर्म, शंकराचार्य, साधु-संतों, माघ मेला और देश का अपमान किया है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार ने शंकराचार्य और साधु-संतों के साथ दुर्व्यवहार किया है। भाजपा को अधिकारियों के माध्यम से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सरकार देश का संविधान, कानून, भाईचारा और परम्परा तोड़ रही है। इस सरकार में किसी के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं हो रहा है।

बस बनी आग का गोला, 3 लोग जिंदा जले, कई झुलसे

नंद्याल। आंध्र प्रदेश के नंद्याल जिले में गुरुवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में कम से कम तीन लोगों की जान चली गई, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सिरिवेल्लमेट्टा गांव के पास एक निजी यात्री बस और कंटेनर ट्रक की आमने-सामने टक्कर के बाद भीषण आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस के अनुसार, एआरबीसीवीआर प्राइवेट ट्रैवल्स की बस नेल्लोर से हैदराबाद जा रही थी और उसमें 36 यात्री सवार थे। सुबह करीब 2 बजे बस का एक टायर अचानक फट गया, जिससे चालक का नियंत्रण बिगड़ गया।

झारखंड में नक्सलियों पर सर्जिकल स्ट्राइक! चाईबासा मुठभेड़ में 15 नक्सली ढेर, 1 करोड़ का इनामी अनल दा भी मारा गया

चाईबासा। झारखंड के चाईबासा जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े अभियानों में से एक को अंजाम दिया है। झारखंड पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई में 15 नक्सली मारे गए हैं। इस मुठभेड़ की सबसे बड़ी सफलता 1 करोड़ रुपये के इनामी नक्सली अनल दा का खात्मा है। यह मुठभेड़ चाईबासा के घने जंगल इलाके में हुई, जब सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी के आधार पर तलाशी अभियान शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान, नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर

फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी भारी जवाबी फायरिंग की। अधिकारियों के अनुसार, गोलीबारी में 15 नक्सली मारे गए। बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद होने की आशंका है। इलाके में अभी भी तलाशी अभियान जारी है और सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है ताकि कोई भी नक्सली भाग न सके। अधिकारियों के मुताबिक, मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। सुरक्षा बलों को अंदेशा है कि कुछ और नक्सली घायल अवस्था में जंगल के भीतर छिपे हो सकते हैं। चाईबासा के इन घने जंगलों में अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि किसी भी नक्सली को भागने का मौका न मिले।

झारखंड में नक्सलवाद की कमर तोड़ने की दिशा में इसे एक ऐतिहासिक सफलता माना जा रहा है। अनल दा जैसे बड़े कमांडर का मारा जाना नक्सली संगठन के लिए एक अपूरणीय क्षति है। राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस सफल ऑपरेशन के लिए जवानों के साहस की सराहना की है।

मुंबई समेत 15 नगर निगम में महिला महापौर होंगी

मुंबई। बीएमसी में मेयर पद महिला को ही मिलेगा। ये साफ हो चुका है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से जुड़े इस बड़े अपडेट के मुताबिक भाजपा-शिवसेना मिलकर महापौर का नाम तय करेंगे। बीएमसी के अलावा नवी मुंबई में भी महापौर पद महिला को मिलेगा, जबकि ठाणे में मेयर अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग से बनेगा। शहरी विकास विभाग ने गुरुवार को लॉटरी के जरिए आरक्षण तय किया, जिसके आधार पर बीएमसी मेयर पद पर महिला की ताजपोशी होगी। महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग ने गुरुवार को एक लॉटरी व्यवस्था के तहत विभिन्न नगर पालिकाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था तय की। शहरी निकाय के नियमों के तहत बीएमसी समेत सभी

नगर पालिकाओं में मेयर पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को रोटेशन प्रणाली के आधार पर दिया जाता है। हालांकि यह आरक्षण व्यवस्था पहले से तय नहीं होती और इसके लिए लॉटरी सिस्टम बनाया गया है। जब तक यह लॉटरी नहीं निकाली जाती, तब तक राजनीतिक पार्टियां मेयर पद के लिए उम्मीदवारों के नाम का एलान नहीं कर सकतीं। संविधान के 74वें संशोधन के बाद नगर निकाय में नेतृत्व के लिए सामाजिक प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। यह लॉटरी व्यवस्था मेयर चुनाव की प्रक्रिया को निष्पक्ष रखने के लिए की गई है।

मध्यप्रदेश भोजशाला विवाद- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बसंत पंचमी पर हिंदू करेंगे पूजा, मुस्लिम पढ़ेंगे नमाज

नई दिल्ली । मध्यप्रदेश के धार जिले में स्थित 11वीं सदी का स्मारक भोजशाला एक बार फिर चर्चा में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए वैज्ञानिक सर्वेक्षणों और अदालती कार्यवाहियों ने इस ऐतिहासिक स्थल से जुड़े विवाद को देश के सबसे चर्चित धार्मिक विवादों में से एक बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के धार में विवादित भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर में हिंदुओं और मुसलमानों को प्रार्थना करने की इजाजत दे दी है। हिंदू समुदाय के सदस्यों को हिंदू त्योहार बसंत पंचमी पर, जो इस साल शुक्रवार को पड़ रहा है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा करने की इजाज़त दी गई है, जबकि मुसलमान दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक अपनी शुक्रवार की नमाज़ पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नमाज़ के लिए आने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या ज़िला प्रशासन को बतानी होगी। कोर्ट ने ज़िला प्रशासन को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के इंतज़ाम करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट हिंदू संगठन, हिंदू

फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें बसंत पंचमी पर हिंदुओं को पूजा करने का विशेष अधिकार देने की मांग की गई थी। HFJ की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने 2 जनवरी को यह अर्जी दाखिल की थी और इसे कोर्ट के सामने अर्जेंट तौर पर पेश किया गया था। अर्जी में कहा गया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 2003 के आदेश में ऐसी स्थितियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जब बसंत पंचमी शुक्रवार की नमाज़ के दिन पड़ती है। उन्होंने 23 जनवरी को पूरे दिन हिंदुओं के लिए खास, बिना किसी रुकावट के पूजा के अधिकार की मांग की। 2003 के ASI के आदेश के अनुसार, मुसलमानों को उस जगह पर दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच शुक्रवार की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, जबकि हिंदुओं को बसंत पंचमी पर पारंपरिक पूजा करने की इजाज़त है और हर मंगलवार को उन्हें खास एक्सेस दिया जाता है। हालांकि, इसमें उन सालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं बताई गई है जब बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती है।